CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

केरल में मिल्क पाउडर प्लांट से बढ़ेगा किसानों का भरोसा

सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ ने 2023 की शुरुआत में केरल के मलप्पुरम जिले के मुरकानाड में एक दूध पाउडर इकाई चालू करने के कदम का स्वागत किया है। इकाई, एक दिन में लगभग एक लाख लीटर दूध को संसाधित करने की क्षमता के साथ, बढ़ती खरीद के मुद्दे को संबोधित करेगी। खासकर मालाबार क्षेत्र में। इसे राज्य सरकार और मालाबार क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के वित्तीय सहयोग से स्थापित किया जा रहा है।

केरल सहकारी दुग्ध विपणन संघ (मिल्मा) के अध्यक्ष के.एस. मणि ने सोमवार को कहा कि संयंत्र की स्थापना 54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से की जाएगी, संभवतः निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण मामूली लागत बढ़ गई है। मिल्मा उसी परिसर में भंडारण और पैकिंग विंग जैसी अन्य सुविधाओं को समायोजित करने के लिए भी काम कर रही है। यह परियोजना की लागत को कम करने में मदद करेगा, श्री मणि ने कहा।

आईसीआरए की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेयरी उद्योग वित्त वर्ष 22 में 9-11% की दर से बढ़ेगा

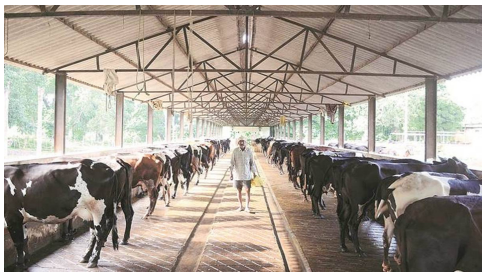

आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार, आर्थिक गतिविधियों में पुनरुद्धार, दूध और दूध उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि, बढ़ते शहरीकरण के कारण आहार संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव से डेयरी उद्योग के 2021-22 में 9-11 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। आईसीआरए ने एक रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में उद्योग-व्यापी मांग 9-11 प्रतिशत बढ़ने की है, जिससे डेयरी उद्योग के लिए लंबी अवधि में एक स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखा गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य मानसून और कुछ क्षेत्रों में फ्लश सीजन की शुरुआत से समर्थित, वित्तीय वर्ष 2021-22 में घरेलू दूध उत्पादन में 5-6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के मध्यम प्रभाव के बाद, उद्योग ने अंत खंडों में खपत में लगातार सुधार देखा गया है।

मेघालय सरकार पशु व्यापारियों को पास जारी करेगी

मेघालय सरकार ने राज्य के उन व्यापारियों को ट्रांजिट पास जारी करने का निर्णय लिया है जो पड़ोसी राज्य असम के माध्यम से पशुओं का परिवहन करते हैं, जहां मवेशियों की आवाजाही पर प्रतिबंध है। हमने पहले ही पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग को ट्रांजिट पास जारी करने का निर्देश दिया है, "उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन तिनसोंग, यह कहते हुए कि इससे राज्य में बाहर से मवेशियों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित होगी।

उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पर्याप्त उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं कि पशु व्यापारियों को बाहर से राज्य में मवेशियों के परिवहन में बाधाओं का सामना न करना पड़े।

ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक ने कटक में मेगा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को कटक जिले के अरिलो-गोविंदपुर में ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (OMFED) द्वारा स्थापित किए जा रहे स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। 244.24 करोड़ रुपये के निवेश के साथ टर्नकी आधार पर स्थापित होने के कारण, संयंत्र का काम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) को सौंपा गया है। इसने नवंबर 2018 में संयंत्र का निर्माण शुरू किया।

ओएमएफईडी ग्राहकों को संयंत्र की स्थापना के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाला दूध और इसके उपोत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही डेयरी किसानों को उनके दूध का उचित मूल्य मिल सकेगा।

सरकार ने प्लांट के लिए ओएमएफईडी को 51 एकड़ जमीन प्रदान की है, जिसमें अरिलो में 18.7 एकड़ और गोविंदपुर में 32.3 एकड़ जमीन शामिल है। पांच लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले इस प्लांट से रोजाना 2 लाख लीटर दूध, 30,000 लीटर दही, 10,000 लीटर छाछ, 5,000 लीटर लस्सी, तीन टन मक्खन, आठ टन घी, तीन टन पनीर, 5,000 लीटर फ्लेवर्ड मिल्क और 20,000 टन मिल्क पाउडर का उत्पादन होगा।

भारतीय स्वाद के लिए उपयुक्त वैकल्पिक प्रोटीन उत्पादों पर काम कर रही है नेस्ले

नेस्ले इंडिया भारतीय बाजार के लिए पौधे आधारित वैकल्पिक प्रोटीन उत्पादों को विकसित करने पर काम कर रही है जो भारतीय स्वाद, संस्कृति और बनावट से परिचित होंगे। हालांकि, कंपनी डेयरी प्रोटीन को प्लांट-आधारित प्रोटीन से बदलने की रणनीति में विश्वास नहीं करती है क्योंकि यह सामाजिक रूप से अनैतिक है।

"वैकल्पिक प्रोटीन और पौधे आधारित प्रोटीन का पूरा क्षेत्र नेस्ले के लिए एक गंभीर मिशन है। हमारे पास वैश्विक स्तर पर 12 अनुसंधान और विकास त्वरक केंद्र हैं जो पौधों पर आधारित प्रोटीन प्रौद्योगिकियों का विकास करते हैं जिन्हें प्रासंगिक उत्पादों के संदर्भ में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। उनमें से एक भारत में मानेसर में है। यह एक ऐसा केंद्र है जो भारत को प्रासंगिक प्रौद्योगिकियां प्रदान करता है," नेस्ले इंडिया के अध्यक्ष सुरेश नारायणन ने कहा।

नेस्ले इंडिया के प्रमुख ने देश में 'प्रोटीन क्लस्टर' स्थापित करने का आह्वान किया। "उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य दालों के साथ-साथ दूध के शीर्ष उत्पादक हैं। हमें किसानों, सरकार, अनुसंधान संस्थानों और निजी खिलाड़ियों के बीच प्रोटीन क्लस्टर बनाने की जरूरत है ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पहले चरण में पौधों पर आधारित प्रोटीन उत्पाद बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए इन समूहों के आसपास आ सकें।

130 करोड़ रुपये का भुगतान न करने पर कर्नाटक आंध्र प्रदेश को दूध की आपूर्ति रोकेगा

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) ने 130 करोड़ रुपये का भुगतान होने तक आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ियों को दूध की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की है और कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि भी की है। यदि कर्नाटक से दूध की आपूर्ति ठप हो जाती है, तो संपूर्ण पोषण योजना के तहत छह साल से कम उम्र के 20 लाख से अधिक बच्चे पौष्टिक भोजन से वंचित हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार नंदिनी ब्रांड के तहत केएमएफ से हर महीने 110 लाख लीटर अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर दूध खरीद रही है।

पिछले चार महीनों से, हालांकि, राज्य सरकार ने केएमएफ को कोई भुगतान नहीं किया, बकाया राशि न केवल 130 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, यहां तक कि दूध की कीमत में संशोधन पर भी विवाद छिड़ गया। जून 2020 में हस्ताक्षर किए गए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते के तहत केएमएफ 5 रुपये प्रति लीटर "वास्तविक लागत से कम" चार्ज कर रहा था क्योंकि संपूर्ण पोषण योजना एक "महान सामाजिक कारण" है। दुग्ध संघों ने हमें सूचित किया है कि वे मौजूदा कीमत पर दूध की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, भुगतान में देरी (आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से) दुग्ध उत्पादकों को अनियमित भुगतान की ओर ले जा रही है", केएमएफ एमडी ने बताया।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चरण - II जम्मू संभाग में शुरू किया गया

पशुपालन विभाग जम्मू ने आज यहां निदेशालय परिसर तालाब टिलो में पशुधन में पैर और मुंह की बीमारी के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रतिष्ठित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के दूसरे चरण का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू प्रांत के सभी जिलों में पैर और मुंह की बीमारी के खिलाफ पूरे पात्र मवेशियों और भैंसों की आबादी का टीकाकरण करना है।

इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ मतलूब अहमद टाक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पशुधन विकास बोर्ड, जम्मू ने किसानों से कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाने और अपने पशुओं को पैर और मुंह की बीमारी के खिलाफ टीकाकरण करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह बीमारी पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास में एक गंभीर बाधा है और डेयरी किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाती है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 11 सितंबर, 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, और 2025 तक पशुधन में एफएमडी और ब्रुसेलोसिस रोगों के नियंत्रण और 2030 तक उनके पूर्ण उन्मूलन की परिकल्पना की गई है।

CEDSI डेयरी, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पृष्ठ 4-6 पर विस्तृत विज्ञापन पढ़ें।

CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

AN INITIATIVE OF AGRICULTURE SKILL COUNCIL OF INDIA

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

Advertisement for Empanelment of Subject Matter Experts (SMEs)

The Centre of Excellence for Dairy Skills in India (CEDSI) is an initiative taken by Agriculture Skill Council of India which aims to ensure sustainability and profitability in the dairy sector through skilling and capacity building, policy advocacy, knowledge management and research. Towards This CEDSI works with stakeholders across the dairy ecosystem including dairy farmers, wage workers, dairy cooperatives and corporates, research, academia, and central and state governments. It strives to be positioned as an innovator and leader in the dairy skilling space across the globe, who undertakes and facilitates applied manpower research in the dairy sector, capacity development in the areas of skilling and provides policy inputs at the national and state level to strengthen skill upgradation.

CEDSI invites applications for the empanelment of (SMEs) on various domains in Dairy, Agriculture and Allied Sectors.

Details mentioned below -

Honorarium: As per CEDSI norms, on availing of the services

Last Date to apply: November 30th, 2021

Application Fee: Free

Master Training Program: The selected candidates may have to undergo a Master Trainer Program

Master Trainer Program Fee: INR 1000 (Virtual Training)

Eligible candidates can apply online through the link - https://bit.ly/cedsi_sme

List of domain sectors -

S. No.	Subject	Sector
1	Livestock Production and Management	**Animal Husbandry**
2	Animal Nutrition	
3	Animal Breeding & Reproduction	
4	Fodder Production and Preservation	
5	Milk Productivity Enhancement	
6	Animal Health, Disease Prevention	
7	Milk Quality Assurance	**Dairy Development**
8	Clean Milk Production	
9	Milk Procurement/Transportation/Chilling	
10	Sales & Marketing of Milk and Milk Products	
11	Organization and Management of Producer Institution	
12	Poultry Production	**Poultry**
13	Poultry Marketing and Processing	
14	Livestock GHG Emission and Mitigation	**Sustainable Dairying**
15	Water Management in Dairy Sector	
16	Waste Management	**Farm Management & Extension**
17	Farm Management/Farm Economics and Accounting	
18	Meat Processing, Preservation Storage and Marketing	**Meat Processing**
19	Value Addition in Meat & Egg Processing	

Candidate must have the following requisites -

- Complete knowledge of Vocational Education, Skill Development ecosystem and its stakeholders.
- Overall sectoral and industry knowledgeability to analyze/collate demand, prepare a sustainable plan/models of skill programs/courses/work-study model and skilling framework and field implementation of the planned activity
- Candidates must not be blacklisted by MSDE/NSDA/NSDC/SSC/UGC or any other institution where he has worked in the past
- For further queries (if any) please write us at **info@cedsi.in**

General Instructions for Applicants (applying for Subject Matter Expert) -

- The Candidate must be a citizen of India.
- Candidates will update their qualifications, experience and other credentials on the CEDSI website/application as and when there is any change.
- All qualifications and experiences will be considered as a cutoff date and, applications will be sent for scrutiny.
- The candidates are advised to satisfy themselves about their eligibility before applying for an SME for a job role in a particular sector. A valid (SMEs) Certificate/Experience Certificate is a must along with other conditions laid down for qualification and experiences in Industry/Sector.
- The prescribed essential qualifications and experience are minimum and mere possession of the same does not entitle a candidate to be enrolled.
- CEDSI may conduct an interview or assessment test if required. No TA/DA shall be paid to the candidates for attending the interview/ assessment test.
- Applications not accompanied with necessary/required documents, self-attested copies of degrees/certificates/experience certificates issued by the competent authority shall be rejected.
- Candidates must regularly visit CEDSI website (www.CEDSI.in) for all the details and updates related to further processes.
- In case of any inadvertent mistake in the process of recruitment/selection, if detected at any stage even after the issue of empanelment order, CEDSI reserves the right to modify/withdraw/cancel any communication sent to the candidates.
- The initial period of empanelment will be for 2 years and can be extended further on the basis of performance and criteria for enrollment.
- CEDSI will engage the expert for training/consultancy/involvement in project implementation and compensation will be given accordingly. Mere empanelment will not be subject to any compensation